

युवाओं के सतत विकास के लिए आजीवन शिक्षा का महत्व: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में

कोमल भारती¹, प्रोफेसर स्वाति सक्सेना²

¹शोध छात्रा, शोध केंद्र, दयानन्द गर्ल्स पी0जी0 कॉलेज, कानपुर उ0प्र0

²शोध— निर्देशिका दयानन्द गर्ल्स पी0जी0 कॉलेज कानपुर, उ0प्र0

Received: 15 April 2025 Accepted & Reviewed: 25 April 2025, Published: 30 April 2025

Abstract

आज के बदलते वैश्विक परिप्रेक्ष्य में युवाओं का सतत विकास केवल औपचारिक शिक्षा तक सीमित नहीं रह गया है। जीवनभर सीखने की अवधारणा अब एक अनिवार्यता बन चुकी है। आजीवन शिक्षा को जीवन भर की जाने वाली सभी सीखने की गतिविधि के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका उद्देश्य व्यक्तिगत नागरिक सामाजिक और रोजगार संबंधी परिप्रेक्ष्य में ज्ञान कौशल और क्षमताओं में सुधार करना है। आजीवन शिक्षा समग्र शिक्षा पर केंद्रित है और इसके दो आयाम हैं सीखने के लिए आजीवन और व्यापक विकल्प। यह सीखने को इंगित करते हैं जो पारंपरिक शिक्षा प्रस्ताव और आधुनिक सीखने के अवसरों को एकीकृत करता है इसमें लोगों को या सीखने के लिए प्रोत्साहित करने पर भी जोड़ दिया आजीवन शिक्षा ज्ञान और अधिग्रहण की एक अलग अवधारणा पर आधारित हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस दिशा में एक दूरदर्शी प्रयास है, जो युवाओं को जीवन के हर चरण में सीखने के लिए प्रेरित करती है। यह शोधपत्र आजीवन शिक्षा की अवधारणा, उसकी आवश्यकता, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इसके समावेशन का विश्लेषण करता है।

कुंजी शब्द- सतत विकास, आजीवन शिक्षा का महत्व, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

Introduction

शिक्षा को एक बड़ी शक्ति के रूप में देखा जाता है एक ऐसी शक्ति जो न केवल राष्ट्रीय विकास में बल्कि आजीवन शिक्षा मनुष्य के सतत विकास में भी योगदान देती है। जो शैक्षिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तथा पर्यावरणीय विकास की कुंजी है। सतत विकास को प्राप्त करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल के विकास को बढ़ावा देती है या आर्थिक कल्याण सामाजिक समानता लोकतांत्रिक मूल्य और बहुत सी चीजों को प्रोत्साहित करती है या बढ़ावा देती है। भारत विश्व की सबसे युवा जनसंख्या वाला देश है, जहां 65 से अधिक जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है। ऐसे में युवाओं के समग्र और सतत विकास के लिए एक लचीली, बहुआयामी, और नवाचारी शिक्षा नीति की आवश्यकता थी, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने पूर्ण किया है। इस नीति में आजीवन शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। यहा नीति शिक्षा को केवल विद्यालय तक सीमित न रखकर एक व्यक्ति के जीवन भर के विकास को बढ़ावा देती है यह नीति सतत विकास लक्ष्य के अनुरूप है जिसका उद्देश्य 2030 तक सभी के लिए समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्तापूर्ण सुनिश्चित करना है।

आजीवन शिक्षा की अवधारणा— युवाओं को जीवन भर सीखने की प्रक्रिया में शामिल करना ताकि वह अपने ज्ञान कौशल और क्षमताओं को विकसित कर सकें और एक बेहतर भविष्य के लिए तैयार हो सकें यह अवधारणा शिक्षा के सभी स्तरों और प्रकारों को जोड़ती है जिसमें औपचारिक, गैर औपचारिक और

अनौपचारिक सभी प्रकार की शिक्षा सम्मिलित है। यह जीवन के सभी चरणों में सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देती है।

सतत विकास— आजीवन शिक्षा युवाओं को सतत विकास के लिए आवश्यक ज्ञान कौशल और दृष्टिकोण प्रदान करती है ताकि वह एक स्थायी भविष्य के लिए काम कर सकें।

समावेशी शिक्षा— आजीवन शिक्षा यह सुनिश्चित करती है कि सभी युवाओं को शिक्षा तक समान पहुंच हो चाहे उनकी पृष्ठभूमि या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो।

व्यक्तिगत विकास— आजीवन शिक्षा युवाओं को अपने व्यक्तिगत विकास के लिए ज्ञान कौशल और क्षमताओं को विकसित करने का अवसर प्रदान करती है ताकि वे आत्मनिर्भर और सफल बन सकें।

सामाजिक विकास— आज जीवन शिक्षा युवाओं को सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूक करती है और उन्हें सामाजिक परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करती है।

आर्थिक विकास— आजीवन शिक्षा युवाओं को और रोजगार और आर्थिक अवसरों तक पहुंचाने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान करती है ताकि वे अपने और अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य बना सकें।

पर्यावरण संरक्षण— आजीवन शिक्षा युवाओं को पर्यावरण के महत्व को बारे में जागरूक करती है और उन्हें पर्यावरण की रक्षा के लिए काम करने के लिए प्रेरित करती है।

वैश्विक नागरिकता— आजीवन शिक्षा युवाओं को वैश्विक मुद्दों के बारे में जागरूक करती है और उन्हें वैश्विक नागरिकता की भावना विकसित करने में मदद करती है।

युवाओं के सतत विकास में आजीवन शिक्षा की विशेषताएं—

1. कैरियर में उन्नति — आजीवन सीखने का मतलब सिर्फ अपनी पुरानी व्यवस्था को बनाए रखना नहीं है या नई भूमिकाओं के लिए भी दरवाजा खोल सकता है यहां तक की एक नई करियर भी उदाहरण भी लिए अगर किसी को आप वर्तमान व्यवसाय में संतुष्ट नहीं है तो आप एक ऑनलाइन कोर्स करके अपने सतत विकास के लिए आजीवन शिक्षा पर विचार कर सकते हैं जो पसंदीदा क्षेत्र में मूल्यवान प्रमाण प्रदान करता है।

2. नई प्रेरणा का विकास — बहुत से लोग समय के साथ अपने कैरियर में रुचि होते हुए पाए हैं नौकरी एक रूटीन बन जाती है जिसमें एक ही दिन एक ही काम को बिना सोचे समझे पूरा करना पड़ता है जो पहले नए और रोमांचक हुआ करता था वह पूर्ण हो जाता है सौभाग्य से आजीवन सीखने से आपका जुनून को फिर से जगाने में मदद मिल सकती है।

4. सॉफ्ट स्किल का विकास — वयस्क सतत विकास सिर्फ आपको जो सिखाती है उससे कई ज्यादा उपयोगी है नई चीज सीखने की प्रक्रिया ही महत्वपूर्ण साफ स्किल को मजबूत करने में मदद करती है जैसे—

- लक्ष्य की स्थापना
- आत्म अनुशासन
- रचनात्मक
- महत्वपूर्ण सूचना
- समय प्रबंधन

— समस्या को सुलझाना

— अनुकूल क्षमता

5. शारीरिक एवं मानसिक विकास — अध्ययनों से पता चला है की आजीवन सीखना से मस्तिष्क के स्वस्थ और कार्य को बेहतर बनाने में मदद मिलती है सीखने से मानसिक लबों में यह शामिल हो सकते हैं

— बेहतर संज्ञानात्मक कार्य

— अधिक समय तक ध्यान देने की क्षमता

— मजबूत स्मृति

— बेहतर तर्क कौशल

6. आत्म सुधार — आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आत्म सुधार बहुत जरूरी है नए कौशल हासिल करके व्यक्ति अपनी क्षमता को उजागर कर सकते हैं और अपने आत्म सम्मान को बढ़ा सकते हैं और जैसे-जैसे वह अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए उन कौशलों का उपयोग करेंगे आपका उद्देश्य और भी बढ़ेगा।

7. नेटवर्किंग के अवसर — व्यावसायिक सतत शिक्षा के लिए कई विकल्पों में परीक्षाओं और शब्द ही शिक्षार्थियों के साथ मिलकर काम करना शामिल है या व्यक्ति को समान विचारधारा वाले पेश करूं से जुड़ने और अपने व्यक्तिगत नेटवर्क को बढ़ाने की अनुमति देता है समय के साथ यह व्यक्ति के करियर को अप्रत्याशित दिशाओं में ले जाने के लिए मूल्यवान अवसर प्रदान कर सकता है भले ही ऐसा ना हो अपने क्षेत्र में एक नया दोस्त बनाना कभी भी नुकसान देह नहीं होता है।

8. समायोजन के गुणों का विकास — आजीवन सीखने वाला आजीवन सीखने में औपचारिक शिक्षा को नियंत्रण पेशेवर और व्यक्तिगत विकास के साथ जोड़ा जाता है जैसे-जैसे तकनीकी तेजी से आगे बढ़ रही है आजीवन सीखने वालों को नए कौशल सीखने होंगे और पेशेवर और व्यक्तिगत वातावरण में तेजी से होने वाले बदलाव के अनुकूल होना होगा

युवाओं के सतत विकास में आजीवन शिक्षा का महत्व—

निरंतर सीखना समय की मांग के अनुसार— वर्तमान समय में तकनीकी और सामाजिक परिवर्तन इतनी तेजी से हो रहे हैं कि केवल प्रारंभिक शिक्षा जीवन प्रारंभिक शिक्षा से जीवन नहीं चल सकता एक युवा को बदलते परिवेश के अनुसार स्वयं को लगातार विकसित करना होता है।

रोजगार के बेहतर अवसर— कंपनियां आज ऐसे कर्मचारियों को पसंद करते हैं जो नई चीज सीखने को तत्पर रहे जो युवा लगातार सीखते रहते हुए अपने कार्य को अच्छी तरह से करते हैं और बेहतर प्रदर्शन करते हैं और तरक्की की राह पर आगे बढ़ते हैं जिससे उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान होते हैं।

व्यक्तिगत विकास— आज जीवन शिक्षा के माध्यम से युवा अपने व्यक्तित्व को बेहतर ढंग से समझते हैं वह आत्मनिरीक्षण संवाद कुशल नेतृत्व और आत्मविश्वास जीवन उपयोगी क्षमताओं का विकास करते हैं उधमिता और नवाचार को बढ़ावा देने में समर्थ है।

तकनीकी कौशल में अद्यतनता— तकनीकी युवाओं को शिक्षा कौशल विकास रोजगार और सामाजिक भागीदारी जैसे क्षेत्र में सशक्त बनाती इससे उन्हें अपने भविष्य के लिए तैयार होने सतत विकास में योगदान देने में मदद मिलती है। ऑनलाइन शिक्षा वेबिनार और वर्चुअल कक्षा शिक्षण को अधिक सुलभ और

समावेशी बनती हैं। तकनीकी शिक्षा प्रशिक्षण युवाओं को तेजी से बदलती तकनीकी दुनिया में कौशल का लगातार नवीनीकरण रोजगार के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करती है आवश्यक है।

नागरिक चेतना और सामाजिक जिम्मेदारी युवाओं को एक उत्तरदायी नागरिक बनने हेतु प्रेरित करना।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आजीवन शिक्षा का प्रावधान:

सभी के लिए शिक्षा— राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करना है, चाहे उनकी उम्र, लिंग, सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि या शारीरिक अक्षमता कुछ भी हो।

बहु-विषयक शिक्षा— यह नीति बहु-विषयक शिक्षा को बढ़ावा देती है, जिससे छात्रों को विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त हो सके और वे विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के लिए तैयार हो सकें।

कौशल विकास पर जोर— यह नीति कौशल विकास पर जोर देती है, जिससे छात्रों को रोजगार के लिए तैयार किया जा सके और वे 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना कर सकें।

शिक्षक प्रशिक्षण यह नीति शिक्षकों के प्रशिक्षण पर भी जोर देती है, ताकि वे छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर सकें।

तकनीक का उपयोग— यह नीति शिक्षा में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देती है, जिससे छात्रों को सीखने के नए अवसर मिल सकें।

अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एबीसी एक डिजिटल प्रणाली है जो छात्रों को उनके उच्च शिक्षा के दौरान अर्जित क्रेडिट को जमा करने, स्थानांतरित करने और उपयोग करने की अनुमति देती है। यह एक वर्चुअल स्टोरहाउस की तरह है जहां छात्रों के क्रेडिट का रिकॉर्ड रखा जाता है, जिससे उन्हें कई प्रवेश और निकास विकल्पों के साथ-साथ क्रेडिट को स्थानांतरित करने और उपयोग करने की सहायता मिलती है।

ओपन लर्निंग और डिजिटल शिक्षा— दीक्षा भारत सरकार द्वारा स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक पहल है। यह शिक्षकों और छात्रों के लिए शैक्षिक संसाधनों की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंचने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। दीक्षा छात्रों को उनकी पाठ्यपुस्तकों और अन्य शैक्षिक सामग्री तक पहुंचने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करने की सुविधा भी प्रदान करता है। दीक्षा छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने और उनके सीखने के अनुभव को बेहतर

स्वयं स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव-लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स— स्वयं एक ऐसा मंच है जो भारत सरकार द्वारा छात्रों को मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। यह छात्रों को विभिन्न विषयों पर उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षिक सामग्री तक पहुंच प्रदान करता है। स्वयं छात्रों को उनकी गति से सीखने और अपनी सुविधा के अनुसार पाठ्यक्रम पूरा करने की अनुमति देता है। यह छात्रों को विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों द्वारा पेश किए जाने वाले पाठ्यक्रमों तक पहुंच प्रदान करता है। स्वयं छात्रों को डिजिटल शिक्षा के लाभों का अनुभव करने और अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने का एक शानदार अवसर प्रदान करता है।

व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण— स्कूली स्तर से ही व्यावसायिक प्रशिक्षण का समावेश। व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण सामान्य शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा को जोड़ना, ताकि छात्रों को पढ़ाई के साथ-साथ कौशल विकास का भी अवसर मिले। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी व्यावसायिक शिक्षा को सामान्य शिक्षा के साथ एकीकृत करने और इसे मुख्यधारा में लाने पर जोर दिया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 की मुख्य विशेषताएँ— समग्र और बहुविषयक शिक्षा छद्म एक कठोर, खंडित शिक्षा प्रणाली से समग्र शिक्षा को बढ़ावा देने वाली शिक्षा प्रणाली में बदलाव पर जोर देती है। यह राष्ट्रीय शिक्षा

नीति कला, मानविकी और विज्ञान के एकीकरण की सिफारिश करती है, छात्रों को विविध विषयों का पता लगाने और अपने उद्देश्य की खोज करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा यह नीति बच्चे के विकास के महत्वपूर्ण शुरुआती वर्षों पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में एकीकृत करके सीखने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करना है। इससे बच्चों के संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक कौशल को कम उम्र से ही बढ़ाने में मदद मिलेगी।

स्कूली शिक्षा की पुनर्कल्पना इसका उद्देश्य वर्तमान 1+2 स्कूली शिक्षा प्रणाली को अधिक लचीली 5+3+3+4 संरचना में बदलना है। पहले पाँच वर्ष आधारभूत शिक्षा पर केंद्रित होंगे, उसके बाद तीन वर्ष प्रारंभिक शिक्षा और चार वर्ष बहुविषयक माध्यमिक शिक्षा पर केंद्रित होंगे। यह दृष्टिकोण वैश्विक मानकों के अनुरूप है तथा अनुभवात्मक शिक्षा एवं आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है।

बहुभाषावाद और भाषा संबंधी प्रवीणता भारत की भाषायी विविधता को पहचानते हुए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हिंदी और अंग्रेजी के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषाओं के शिक्षण को प्रोत्साहित करता है। यह कदम न केवल सांस्कृतिक समावेशिता को बढ़ावा देता है बल्कि छात्रों में भाषा प्रवीणता और संचार कौशल को बेहतर बनाने का भी लक्ष्य रखता है।

मूल्यांकन सुधार नीति का उद्देश्य मूल्यांकन के लिए रटने की आदत को योग्यता आधारित दृष्टिकोण से बदलना है। यह छात्रों की प्रगति को केवल अंकों के बजाय उनकी समझ और समस्या समाधान क्षमताओं के आधार पर मापने के लिए रचनात्मक और निरंतर मूल्यांकन को प्रोत्साहित करता है।

भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक परख राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया है, जो मूल्यांकन में बहुप्रतीक्षित एकरूपता लाएगा। डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देना: शिक्षा की पहुँच और गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, डिजिटल संसाधनों और ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म के उपयोग पर जोर देता है। इससे डिजिटल डिवाइड के अंतर को कम करने में मदद मिलेगी और यह सुनिश्चित होगा कि सभी क्षेत्रों के छात्रों को शैक्षिक अवसरों तक समान पहुँच मिले।

उच्च शिक्षा सुधार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुविषयक और लचीली उच्च शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना की गई है। इसका उद्देश्य अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना, रचनात्मकता को बढ़ावा देना और शिक्षा जगत और उद्योग के बीच मजबूत संबंध स्थापित करना है। यह नीति विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए भारत में परिसर स्थापित करने का मार्ग भी प्रशस्त करती है, जिससे अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा मिलता है।

शिक्षक सशक्तीकरण युवा दिमागों को आकार देने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए, छम्ह का उद्देश्य शिक्षक प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास को बढ़ाना है। यह अधिक शिक्षार्थी-केंद्रित शैक्षणिक दृष्टिकोण को भी प्रोत्साहित करता है और शिक्षकों के रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच कौशल को पोषित करने पर अधिक जोर देता है।

लिंग और सामाजिक समावेशन राष्ट्रीय शिक्षा नीति समावेशिता के महत्व पर जोर देती है, जिसका लक्ष्य शिक्षा में लैंगिक और सामाजिक अंतर को कम करना है। यह लिंग, जाति या आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।

अधिक लचीलापन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ढाँचे के भीतर मल्टी एंट्री और मल्टीपल एग्जिट विकल्पों का कार्यान्वयन **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020** का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो छात्रों को उनके शैक्षिक मार्गों में अधिक लचीलापन और विकल्प प्रदान करता है।

समग्र विकास राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 छात्रों के समग्र विकास पर केंद्रित है, जो उनके संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक विकास को संबोधित करता है। यह आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देता है तथा छात्रों को 21वीं सदी में सफल होने के लिए तैयार करता है।

कौशल विकास 2020 कौशल विकास पर जोर देती है, छात्रों को 21वीं सदी के कौशल जैसे कि आलोचनात्मक सोच, संचार, समस्या समाधान और डिजिटल साक्षरता से लैस करती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित मुद्दे

मानकीकृत अंतर-संचालनीय एवं गतिशीलता आधारित उच्च शिक्षा

पारिस्थितिकी तंत्र क्रेडिट आधारित आठ सेमेस्टर प्रारूप का उद्देश्य ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है, जहाँ छात्र सैद्धांतिक रूप से अपने क्रेडिट को कहीं भी स्थानांतरित कर सकें, जिससे सार्थक शैक्षणिक कार्य में उनकी सहभागिता प्रभावित हो।

शिक्षा ग्रहण करने और पारस्परिक आदान-प्रदान करने, सीखने, आत्मसात् करने, मूल्यांकन करने और आलोचनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करने का कार्य है। हालाँकि, उच्च शिक्षा की यह पुनर्कल्पना शिक्षा को बाजार में जीवित रहने के साधन के रूप में देखती है, जिसकी एक बड़ी कीमत जुड़ी हुई है।

पाठ्यक्रम में कटौती क्रेडिट आधारित प्रणाली (जहाँ संरचना विषय-वस्तु को निर्धारित करती है, न कि इसके विपरीत, जैसा कि होना चाहिए) के परिणामस्वरूप सभी विषयों में पाठ्यक्रम छोटा हो गया है।

मुख्य पाठ्यक्रम का कमजोर होना. शिक्षण पद्धति की सबसे बड़ी समस्या मुख्य विषय का कमजोर होना है, जिससे विशेष ज्ञान प्राप्ति पर असर पड़ता है।

विषय की मूल विषय-वस्तु को कमजोर करके, डोमेन-केंद्रित ज्ञान वितरण और अवशोषण के मानकों को कम कर रहा है।

उदाहरण कोलकाता के सेंट जेवियर्स विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र ऑनर्स के लिए, आठ पाठ्यक्रमों में से केवल एक ही सीधे तौर पर ऑनर्स विषय से संबंधित है, जबकि बाकी पाठ्यक्रम मानव व्यवहार और मीडिया अध्ययन जैसे विशिष्ट ज्ञान के विभिन्न अन्य क्षेत्रों को कवर करते हैं।

छात्रों पर मूल्यांकन का बोझ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत, छात्रों को कई आंतरिक मूल्यांकनों के साथ प्रति सेमेस्टर सात से आठ परीक्षाएँ देनी होती हैं।

इसके साथ ही अलग-अलग उपस्थिति के लिए अंक और निरंतर मूल्यांकन कक्षाओं में भाग लेने के लिए अंकों को मिलाकर, एक बड़ा नौकरशाही भार (छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए) पैदा होता है।

कला विषयों में प्रैक्टिकल परीक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत, गैर-मुख्य कला विषयों के लिए भी प्रैक्टिकल निर्धारित किए गए थे, जो अव्यावहारिक है। हालाँकि, गैर-मुख्य विषयों के लिए व्यावहारिक परीक्षा आयोजित करने की अव्यवहारिकताओं का सामना करने के बाद, दिल्ली विश्वविद्यालय ने हाल ही में इसे हटा दिया।

कार्यान्वयन और संसाधन आवंटन इस नीति की सफलता सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढाँचे की कमी, अपर्याप्त धन और प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी जैसे मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

डिजिटल विभाजन हालाँकि यह नीति शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर देती है, मौजूदा डिजिटल विभाजन, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में और सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों के बीच, प्रौद्योगिकी संचालित शिक्षण समाधानों के न्यायसंगत कार्यान्वयन में बाधा बन सकता है।

निगरानी और मूल्यांकन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्राप्त करने की दिशा में अपनी प्रगति का आकलन करने के लिए एक स्पष्ट निगरानी और मूल्यांकन तंत्र का अभाव है।

सतत विकास लक्ष्य एस.डी.जी. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बारे में है। एस.डी.जी.का पूरा शीर्षक है "समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना"।

मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल नई शिक्षा नीति के तहत डम्डम् प्रणाली को लागू करने में भारतीय संस्थानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

रिपोर्ट के अनुसार, हालाँकि एक लचीली प्रणाली की तरह दिखती है, जिसे पश्चिमी शैक्षणिक संस्थानों द्वारा प्रभावी ढंग से संचालित किया जा रहा है, लेकिन यह देश में अच्छी तरह से कार्य नहीं कर सकती है।

राज्य की भूमिका और पहुँच राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना का उद्देश्य पात्र राज्य उच्च शैक्षणिक संस्थानों को रणनीतिक वित्त पोषण प्रदान करना है। राज्य की योजनाओं के आलोचनात्मक मूल्यांकन के आधार पर उच्च शिक्षण संस्थानों को रणनीतिक वित्त पोषण प्रदान करना।

वित्तीय बाधाओं, भौगोलिक बाधाओं, हाशिए पर रहने वाले वर्गों के छात्रों द्वारा सामना किए जाने वाले रुढ़िवादी खतरे आदि के कारण सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में उच्च शिक्षा तक सीमित पहुँच है।

भाषा संबंधी मुद्दे: अधिकांश उच्च शिक्षा संस्थान मुख्य रूप से अंग्रेजी को शिक्षण माध्यम के रूप में उपयोग करते हैं और स्थानीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करने वाले उच्च शिक्षा संस्थानों की कमी है। इससे गैर-अंग्रेजी भाषी लोगों का बहिष्कार होता है, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय अलगाव होता है और आर्थिक असमानताएँ बढ़ती हैं।

वित्तपोषण की कमी: शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को जल्द-से-जल्द सकल घरेलू उत्पाद के 2035 तक 50/ पहुँचने की आवश्यकता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, कुल शिक्षा परिव्यय सकल घरेलू उत्पाद का 6.4% है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रमुख पहल— प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया स्कूलों में उच्च-गुणवत्ता, न्यायसंगत और आनंदमय शिक्षा प्रदान करेगा।

निपुण भारत का लक्ष्य वर्ष 2026-27 तक कक्षा 3 के अंत तक सार्वभौमिक आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता सुनिश्चित करना है।

प्रधानमंत्री ई-विद्या दीक्षा जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देगा और छात्रों को ई-बुक और सामग्री प्रदान करेगा। उसे 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए खेल आधारित शिक्षा के लिए फाउंडेशनल स्टेज और जादुई पिटारा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। भारत में शिक्षकों और स्कूल प्रिंसिपलों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के लिए निष्ठा। डिजिटल प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा अनुप्रयोगों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला फ्रेमवर्क। क्रेडिट हस्तांतरण और शैक्षणिक लचीलेपन को सुविधाजनक बनाने के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क जैसे

विभिन्न शैक्षणिक फ्रेमवर्क की शुरुआत। विश्व स्तरीय संस्थान योजना, किफायती, उच्च कोटि की शैक्षणिक और शोध सुविधाएँ सृजित करने के लिए, 'प्रतिष्ठित संस्थानों' का नामकरण।

वैश्विक शैक्षणिक नेटवर्क पहल का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिकों और उद्यमियों की प्रतिभा का दोहन करना है, ताकि भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ उनके जुड़ाव को प्रोत्साहित किया जा सके, ताकि देश के मौजूदा शैक्षणिक संसाधनों को बढ़ाया जा सके, गुणवत्ता सुधार की गति को बढ़ाया जा सके और भारत की वैज्ञानिक तथा तकनीकी क्षमता को वैश्विक उत्कृष्टता तक बढ़ाया जा सके।

शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने की योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रासंगिकता की समस्याओं को संयुक्त रूप से हल करने के लिए भारतीय संस्थानों तथा दुनिया के 28 चयनित देशों के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों के बीच शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग की सुविधा प्रदान करके भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार करना है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

वित्तीय बाधाएँ— एनईपी 2020 को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता है, जो सभी राज्यों और संस्थानों के लिए उपलब्ध नहीं हो सकती हैं।

शिक्षकों की कमी— विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षित और योग्य शिक्षकों की कमी एक बड़ी चुनौती है।

शिक्षण विधियों को अपनाने में कठिनाई— शिक्षकों को नई शिक्षण विधियों और तकनीकों को अपनाने में समय और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है।

संसाधनों की असमानता— विभिन्न क्षेत्रों और संस्थानों के पास समान रूप से संसाधन उपलब्ध नहीं हैं, जिससे कार्यान्वयन में असमानता हो सकती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँच— ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा तक पहुँच और बुनियादी ढाँचे की कमी एक महत्वपूर्ण चुनौती है।

भाषा— स्थानीय भाषाओं में शिक्षा सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी एक चुनौती है।

जागरूकता और प्रशिक्षण— एनईपी 2020 के बारे में जागरूकता और शिक्षकों और छात्रों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करना भी महत्वपूर्ण है।

सुझाव

डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना

सार्वजनिक—निजी भागीदारी मॉडल को प्रोत्साहन

कौशल आधारित पाठ्यक्रमों का सुदृढीकरण

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन

निष्कर्ष— राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आजीवन शिक्षा को युवाओं के समग्र विकास का आधार मानती है। यदि इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाए तो यह भारत को वैश्विक ज्ञान अर्थव्यवस्था में अग्रणी बना सकती है। आजीवन शिक्षा के माध्यम से युवा न केवल तकनीकी दृष्टि से सक्षम होंगे, बल्कि सामाजिक और मानवीय मूल्यों से भी समृद्ध होंगे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली में सकारात्मक परिवर्तन लाना है, लेकिन इसके पक्ष और विपक्ष का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना आवश्यक है। शिक्षा में सार्थक सुधारों के लिए

हितधारकों का इनपुट महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को बेहतर बनाने के लिए, इसकी क्रेडिट आधारित प्रणाली का पुनर्मूल्यांकन करने, मुख्य विषयों पर जोर देने और गैर-मुख्य पाठ्यक्रमों को समाप्त करने की आवश्यकता है।

सन्दर्भ सूची—

- अटचोअरेना ,डी. 2018 आजीवन शिक्षा और सतत विकास लक्ष्य ।
- बैडेस्कू ,एम .और सैसाना ,एम. (2008), आजीवन शिक्षा में भागीदारी ।
- डेलर्स , जे ., एट अल . (1996) भीतर का खजाना : 21 वीं सदी के लिए शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग की यूनेस्को को रिपोर्ट ,पेरिस :यूनेस्को ।
- करमन, बी.(2012) जीवन सिखाने के सन्दर्भ में हमारे देश की राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में कला शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के अवसर ।
- हर्सेन, सी.(2011) आजीवन सीखने के दृष्टिकोण के प्रति शिक्षकों के दृष्टिकोण, दृष्टिकोण और योग्यताओं का अध्ययन
- एस्पिन,डी , चौपमैन,जे.डी.(2001) आजीवन शिक्षा : अवधारणाएं इंटरनेशनल जर्नल ऑफ लाइफ लॉन्ग एजुकेशन ।
- लाइमैन, हेलेन ,सार्वजनिक पुस्तकालयों में व्यस्क शिक्षा गतिविधियाँ (शिकागो: अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन 1954)
- शर्मा, ताराचन्द्र (2004) आजीवन सीखने का मतलब नहीं दिल्ली : सरूपएंड संस पृ.56
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020